विवरण

नई शिक्षा नीति में राष्ट्रीय एकता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के आधारभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने स्कूल शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क (नेशनल करिक्यूलम फ्रेमवर्क) तैयार किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास संवैधानिक दायित्व, भारत की सामान्य सांस्कृतिक विरासत तथा राष्ट्रीय पहचान के लिए आवश्यक अन्य तत्वों से युक्त सामान्य महत्वपूर्ण विषय होंगे । फ्रेमवर्क के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए रा०शै०अ०प्र०प० ने स्कूल पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों में संशोधन किये । रा०शै०अ०प्र०प० के संशोधित पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों के आधार पर राज्य एजेंसियों ने भी स्कूली पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या/पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने और चरणबद्ध तरीके से उन्हें स्कूल प्रणाली में लगाने के लिए कदम उठाए हैं । इसके अतिरिक्त, रा०शै० अ०प्र०प० का एक सतत मूल्यांकन कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत राज्य स्तरीय एजेंसियों और प्राइवेट प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की साम्प्रदायिक सद्भाव, धर्म-निरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से समीक्षा की जाती है ।

कालेज/विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के सम्बन्ध में कोई केन्द्रीयकृत प्रणाली नहीं है । प्रत्येक विश्वविद्यालय शैक्षिक दृष्टि से स्वायत्त है और अध्ययन के अपने पाठ्यक्रम निर्धारित करता है । हालांकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक ऐसी स्कीम है जिसमें प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम को समाज के लिए अधिक संगत बनाने के लिए पाठ्यक्रमों को पुनर्निर्धारित किया जा सकता है । इसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति तथा भारत में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास जैसे विषयों के सम्बन्ध में जागरूकता लाना शामिल है ।

Representation from All India Research Associates Association

2572. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

SHRI N. E. BALARAM:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOMENT be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation from the All India Research Associates Association, Varanasi;

(b) if so, what are the demands contained therein; and

(c) the decision taken by Government thereon?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) to (c) Yes, Sir. The Convenor of the All India Research Associates Association had submitted a Memorandum regarding demands of Research Associates working in different Universities and Research Institutes of the country. The main demands of the Association are:—

—The Research Associates should be granted allowances such as DA and CCA w.e.f. 1-4-1987.

—Research Associates should be given first priority in recruitment to various posts in Universities, Research Institutes and various Departments of the Government.

—The experience of a candidate as Research Associate should be taken into account for recruitment for regular jobs.

—All funding agencies should adopt uniform Rules and Regulations regarding tenure and other service conditions of Research Associates.

—Working conditions and leave rules of Research Associates should be at par with teachers|scientists of Universities and Research Institutes.

—The Research Associateship should be for a period of six years in the first instance.

—The scale of remuneration of Research Associates should be revised alongwith revision of salaries of Central Government employees.

According to the information furnished by UGC, a Committee consisting of representatives of various funding agencies viz., Department of Science and Technology, Council of Scientific & Industrial Research, Indian Council of Agricultural Research and Indian Council of Social Sciences Research, considered the above demands. The Committee could not agree to the demands on the following grounds:—

—Associateship cannot be considered as regular employment and hence, the demand for payment of DA and CCA is not justified.

—Research experience is considered for selection to faculty positions and the period of Research Associateship cannot be counted as service rendered in an organised cadre;

—Research Associateship is awarded to an individual for pursuing post-doctoral research on an approved time-bound project and the tenure is coterminus with the project.

—Rules and Regulations of project funding agencies are already similar with minor variations according to the needs of the concerned organisation.

—Maximum tenure under the UGC Research Associateship should be limited to a total period of five years. However, at the time of extension of Research Associateship for two years beyond three years, UGC may consider upgradation of Associateship to the next higher slab, if the work is found to be good.

पाठ्य पुस्तकों में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम

2573. **कुमारी आलिया :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्यालयों में लगी कुछ पाठ्य पुस्तकों में से सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हटा दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) नई पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और उनके इतिहास से अवगत कराने के लिए क्या नए परिवर्तन किए जाने और कदम उठाए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (**श्री अर्जुन सिंह**) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा विकसित किया गया जिसमें कोर पाठ्यचर्या विषय के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के अध्ययन को शामिल किया गया है जिसमें स्कूली पाठ्य-पुस्तकों में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को उपयुक्त स्थान दिया गया है ।

Mid-day meal scheme

2574. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to introduce "National Mid-Day Meal Scheme" for elementary schools children through-out the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?